राज्य स्तरीय बैंकर्स स मति, उत्तराखंड
53वीं बैठक दिनांक 01 जून, 2015 का कार्यवृत्त

उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में संपन्न की गयी। इस बैठक में भारतीय रिजर्व समस्त बैंक / बीमा कंपनी एवं शासकीय वभागों के शीर्ष अधकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

श्री पल्लव महापात्रा, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक ने एस.एल.बी.सी. की 53वीं बैठक में नाबार्ड का हार्दिक अभनन्दन कया और उपस्थित सभी प्रतिभागयों का स्वागत कया।

प्रधानमंत्री बीमा एवं पेंशन योजनाएं :

उन्होंने सभी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा क समस्त बैंकों एवं बीमा कंपनियों के सहयोग से प्रधानमंत्री जन-धन योजना की सफलता के उपरांत इसके द्वतीय चरण में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजनाओं को सफल बनाते हुए अब तक 9,45,126 व्यक्तियों का पंजीकरण कया जा चुका है और इनकी प्रीमयम राश को दिनांक 01 जून, 2015 से खाताधारकों के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट करना आरम्भ हो गया है।

ATM-RuPay-Debit Card

उन्होंने सभी बैंकों से कहा क पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए खातों हेतु ग्राहकों को **ATM-RuPay-Debit Card** जारी करें और उन्हें कैम्प मोड में **PIN** नंबर के साथ पासबुक देना भी सुनिश्चित करें।

ब्रॉड बैण्ड कनेक्टि वटी या वैकल्पिक व्यवस्था

उन्होंने कहा क यद्यप बैंकों द्वारा सभी परिवारों से खाते खोले जा चुके हैं परंतु अधकतर क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिवटी न होने के कारण वहाँ पर ऑन-लाइन इसलए भारत सरकार एवं बी.एस.एन.एल. से अनुरोध कया क राज्य के शेष 1397 एस.एस.ए. में टेलीकॉम कनेक्टिवटी उपलब्ध कराएं ताक बैंक / बी.सी. के माध्यम से प्रदेशवासयों को ऑन-लाइन बैंकंग सेवाएं प्रदान करायी जा सके।

ऋण-जमा अनुपात

उन्होंने सदन को बताया क राज्य का ऋण-जमा अनुपात पछली तिमाही के 58.37 जिसके लए सभी बैंकों को धन्यवाद देते हुए कहा क उन्हें पहाड़ी जिलों का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु सार्थक प्रयास करना होगा।

वा र्षक ऋण योजना

उन्होने आगे कहा क इस वर्ष अत्यधक वर्षा होने के बावजूद भी समस्त बैंकों ने वार्षक ऋण योजना वर्ष 2014-15 के निर्धारित लक्ष्य ` 12,505 करोड़ के सापेक्ष 2015 तक ` 10,408 करोड़ की उपलब्धि दर्ज की है जोक लक्ष्य का 83 % है।

आरसेटी संस्थान

पथौरागढ़ एवं चम्पावत जिलों में आरसेटी संस्थान हेतु भूम आवंटन / हसतांतरण कया जाना बहुत समय से लम्बित है और उन्होंने सदन को अवगत कराया क भारत सरकार ने प्रायोजक बैंकों को निर्देशत कया है क वे संस्थान हेतु भवन 2015 तक चयनित भूम अनिवार्य रूप से प्रायोजक बैंक को उपलब्ध करा दी जाए।

<u>आपदा – राहत</u>

अत्यधक वर्षा एवं आँधी-तूफान से फसलों को हुई व्यापक क्षति को दृष्टिगत नाबार्ड एवं राज्य सरकार के संबंधत वभागों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषत कया गया है।

<u>बैंक द्वारा भू म अ भलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार का सृजन</u>

<u>(On-line Creation of Charge on Land by Banks for Agri loans)</u>

राज्य सरकार से अनुरोध कया क भूम अभलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार का सृजन जिसको उपयोग करने हेतु बैंकों को अनुमति प्रदान की जाए।

इसी प्रकार बैंकों द्वारा जारी कए गए वसूली प्रमाण पत्रों को भी शासन के वेब पोर्टल पर ऑन-लाइन फाइलंग करने की सुवधा प्रदान की जाए।

मीडया एवं वभन्न डेवलपमेन्टल एजेन्सियों का राज्य के वकास एव ऋण प्रवाह को गति देने के लये आह्वान कया।

<u>श्री राकेश शर्मा, अपर मुख्य स चव, उत्तराखंड शासन</u>

उत्तराखंड शासन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा क प्रधानमंत्री जन-धन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजनाओं को सफल बनाने में समस्त बैंकों ने सकारात्मक एवं सराहनीय कार्य कया है। राज्य का ऋण-जमा अनुपात 60 % होने पर संतोष प्रकट कया और कहा क अभी कई बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 40 % से कम है जिसे बढ़ाने हेतु वशेष रणनीति के तहत कार्य करना होगा। आगे कहा क इस तिमाही में भी मैदानी जिलों का ऋण-जमा अनुपात हमेशा की तरह पहाड़ी जिलों से अधक रहा है अर्थात बैंक पहाड़ी जिलों में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु समुचत कार्य नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने असंतोष प्रकट कया क अभी तक बैंकंग सेवराहित एस.एस.ए. में ब्रॉड बैण्ड / वाई.-मैक्स कनेक्टिवटी नहीं पहुँच पाई है जिसके लए उन्होंने बी.एस.एन.एल. के अधकारियों से कारण जानना चाहा। बी.एस.एन.एल. ने बताया क बैंकों के 1397 एस.एस.ए. / क्लस्टर में से 216 क्लस्टर में टेलीकॉम कनेक्टिवटी (40 में ब्रॉड बैण्ड और 176 में वाई.-मैक्स) पहुँचा दी गयी है और आगामी वर्षों के प्रथम चरण में 119 क्लस्टर तथा द्वतीय चरण में 458 क्लस्टर में यह सुवधा उपलब्ध कराना प्रस्तावत है और अन्य शेष क्लस्टर्स के लए निगम जिसके लए उन्होंने राज्य सरकार एवं बैंकों से फण्ड उपलब्ध कराने हेतु आग्रह कया।

VSAT के **Shared Band Width Basis** माध्यम से टेलीकॉम कनेक्टिवटी उपलब्ध कराई जा सकती है जिसकी अनुमानित लागत अलग-अलग **VSAT** लगाने की तुलना में सस्ता पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा क केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग के भारतीय स्टेट बैंक ने अध्यक्ष महोदय को आश्वासन दिया क 30 जून, 2015 तक सोनप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ए.टी.एम. स्थापत कर दिया जाएगा।

आगे अपर मुख्य सचव ने कहा क चीन की सीमा से लगे पथौरागढ़ जिला में ताक वहाँ से व्यापार करने हेतु मुद्रा की पर्याप्त उपलब्धतता हो सके। इसी क्रम भारतीय स्टेट बैंक ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया क गुँजी में प्रत्येक वर्ष छः माह के लए (01 जून से) भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा बैंकंग सेवाएं प्रदान करायी जाती है।

उन्होंने संबंधत बैंकों को आश्वासन दिलाया क जहाँ अभी तक आरसेटी संस्थान 2015 तक संबंधत वभागों के सचव द्वारा भूम हस्तांतरित करने हेतु जिलाधकारी को प्रशासनिक अनुमति दे दी जाएगी। उन्होंने उत्तराखंड सचवालय में पदस्थापत वत्त (बैंकंग) को निर्देशत कया क शासन स्तर पर बैंकों से संबंधत सभी लम्बित मामलों को संबंधत वभागों से मलकर निपटान करवाना सुनिश्चित करें।

स्वरोजगार योजना के अंतर्गत होटल निर्माण के लए दिए जाने वाले बैंक ऋण हेतु ग्रामीण क्षेत्र की कृष भूम को व्यवसायिक भूम में परिवर्तित करने संबंधी

उपलब्ध करा दिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा क बैंक द्वारा भूम अभलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकत करने हेतु सॉफ्टवेयर का सक्योरिटी ऑडट शीघ्र ही राजस्व वभाग द्वारा कए जाने के उपरांत बैंकों के प्रयोग हेतु नोटिफकेशन जारी कर दिया जाएगा।

इस बैठक के एजेण्डा संख्या - 13 के संदर्भ में उन्होंने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को निर्देशत कया क खरीफ एवं रबी की नोटिफाइड क्रॉप को बीमत करने हेतु अधसूचना आगामी वर्षों के लए एक साथ ही जारी कर दी जाए और यदि कसी तब उसके लए अलग से परिपत्र जारी कया जाए।

अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं राज्य सरकार के संबंधत वभागों को निर्देशत कया क जितने भी लम्तिब मामले हैं उन्हें आपसी सहयोग से निपटाएं और अगर कोई समस्या हो तो हम से संपर्क करें।

<u>श्री सी. पी. मोहन, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड</u>

हो रहा है क बैंकों द्वारा द्वारा दिए जाने वाले कृष सावध ऋण (एग्रीकल्चर टर्म है।

उन्होंने कहा क वगत में आयी प्राकृतिक आपदा से कृष क्षेत्र प्रभावत हुआ है जिसके कारण अधकतर कसानों के फसल उत्पाद को क्षति हुई है। इसलए सभी बैंकों से अनुरोध है क प्रभावत कसानों को पुन: नए कृष साख ऋण वतरित करें।

उन्होंने आगे कहा क जिस प्रकार स्वयं सहायता समूह गठित करवाने पर उसी प्रकार यदि बैंक भी एस.एच.जी. का गठन कर उनका बैंक लंकेज करने के उपरांत नाबार्ड को सूचत करें तो बैंक शाखाओं को भी प्रोत्साहन राश प्रदान की जाएगी।

श्री बी. एस. भण्डारी, सदस्य, पी.एफ.आर.डी.ए.

नई दिल्ली ने सदन को अटल पेंशन योजना से संबंधत वस्तृत जानकारी प्रदान की और पवार प्वांइट के माध्यम से बैंकों को इस योजना के क्रयान्वयन और प्रचार-प्रसार में आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी प्रस्तुत कया।

श्री बिश्वा केतन दास, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी शीर्ष अधकारियों को 53वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में पधारने एवं मार्गदर्शन देने के लये हार्दिक धन्यवाद कया। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह कया क स्वयं सहायता समूहों को अधक से अधक ऋण स्वीकृत एवं वतरित कये जायें। उन्होंने सदन को अवगत कराया क दिनांक उत्तराखंड ने समस्त सदस्य बैंकों को अपने त्रैमासक आँकड़ों को सीधे एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट (www.slbcutarakhand.com) पर ऑन-लाइन प्रेषण करने की सुवधा उपलब्ध करा दी है।

सहयोगी बैंकों एवं बीमा कंपनियों से आये अधकारियों का सहयोग एवं सहभागता के लये धन्यवाद कया।

****